



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938

No. 431]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 474(अ).—जबकि, आधार का उपयोग करने से सेवाएं या लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इनमें पारदर्शिता एवं दक्षता आती है और लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सहज और निर्बाध तरीके से सीधे मिलती है और आधार से व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने के लिए एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

और जबकि, राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (उक्त योजना), भारत की समेकित निधि से बहन किया जाने वाला व्यय है।

अतः, अब, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा (7) के प्रावधानों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (1) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को एतद्वारा बच्चों द्वारा आधार धारित करने अथवा आधार प्रमाणन का प्रमाण देना अपेक्षित है और योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के संवितरण को बच्चे के आधार के धारण अथवा आधार प्रमाणन की प्रक्रियाधीन, जैसा मामला हो, से जोड़ा जाएगा और बच्चे से आधार प्रपत्र संग्रह अथवा उन्हें प्रमाणित करने का दायित्व, बच्चे के अभिभावकों या अभिरक्षकों के समन्वय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य का होगा।
- उक्त योजना के तहत लाभ लेने वाले ऐसे बच्चों को, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की पात्र है, विद्यालय का प्राचार्य यह सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि इन बच्चों को उनके आधार नामांकन के लिए निकटतम आधार नामांकन केन्द्र (सूची "www.uidai.gov.in" पर उपलब्ध हैं) पर ले जाया जाए।
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य ने विद्यालय शिक्षा विभाग अथवा इस योजना का संबंधित विभाग (यहां इसके बाद "विभाग" कहा गया है) को ऐसे बच्चों के लिए नामांकन सुविधाएं देना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र

अवस्थित नहीं है, विभाग, यूआईएडीआई के मौजूदा पंजीयकों के संबंध में किसी सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधाएं मुहैया कराएगा या यूआईएडीआई पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक बच्चे को आधार आवंटित किया जाए, बच्चे को, बच्चे अथवा अभिभावक अथवा अधीरक्षक, जैसा मामला हो द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जाएगी।

(क) (i) यदि बच्चे ने नामांकन किया है, उसके आधार नामांकन पहचान स्लिप; अथवा

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके आवेदन की छायाप्रति, जैसा पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है

(ख) (i) फोटोग्राफ सहित बैंक की पासबुक; अथवा (ii) स्कूल के प्राचार्य अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र; अथवा (iii) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2 (1) लाभार्थियों को सहज और निर्बाध सॉफ्टवेयर या लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपने क्षेत्रीय एककों और विद्यालयों के जरिए निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, नामतः:

(2) बच्चों और उनके अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को उक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया और विद्यालयों में व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को परामर्श दिया जाए कि यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं कराया है, अपने बच्चों का अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन कराने के लिए 30 जून, 2017 तक नामांकन कराएं।

(3) यदि लाभार्थी विद्यालय अथवा अपने निवास स्थल के आस-पास नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण वे नामांकित होने की वजह से नामांकन नहीं करा पाए हों, विभाग से अपेक्षा है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा सृजित करें और बच्चों और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने वेब-पोर्टल पर अपने नाम और अन्य ब्यौरा जैसे स्कूल का रोल नः अथवा कक्षा विवरण, विद्यालय का नाम, पता, मोबाइल नः देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध पंजीकृत करें और ये अनुरोध पंजीकृत विद्यालयों के पास भी पंजीकृत किए जाएं।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू- कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-5/2016-एस एस (खंड-II) पार्टी]

डी. के. गोयल, उप-सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017.

S.O. 474(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (the said Scheme) is an expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section (7) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Children receiving benefit under the aforesaid Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication and the disbursement of scholarship amount under the aforesaid Scheme shall be linked to possession of Aadhaar by the children or had undergone Aadhaar authentication, as the case may be, and the responsibility to collect Aadhaar from children or to authenticate them, as the case may be, shall be on the Principal of the School concerned, in coordination with parents or guardians of the children.

2. Children receiving benefits under the aforesaid Scheme who are not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, and in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, the Principal of the School shall ensure and make arrangement to ensure that such children are taken to the nearest Aadhaar Enrolment Center (list available at "www.uidai.gov.in") for enrolling them for Aadhaar.

3. As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the School Education department or the department dealing with the aforesaid Scheme in the State (herein after called 'department') is required to offer enrolment facilities for the children who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar Enrolment Centers located in the vicinity, the department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIADI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the children, scholarship amount shall be sanctioned to the children, subject to the production of the following documents by the child or the parent or guardian, as the case may be, namely :-

- (a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Photo Identity Card issued by the Principal of the School or Tehsildar; or (iii) any other document specified by the State Education Department.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free subsidy or benefits to the beneficiaries, department through their field units and schools shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(2) Wide publicity through media and individual notices at schools shall be given to children and their parents or guardians to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the scholarship amount under the aforesaid Scheme and the parents or guardians may be advised to get their children enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within vicinity from the school or where they reside, the department is required to create enrolment facilities at convenient locations and the children and their parents or guardian may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, school roll number or class details, school name, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered with the registered schools.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-5/2016-SS (Vol.II) Pt.]

D. K. GOEL, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 475(अ).—जबकि, सेवाएं या लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इनमें पारदर्शिता एवं दक्षता आती है और लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सहज और निर्बाध तरीके से सीधे मिलती है और आधार से व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने के लिए एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

और जबकि, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना (योजना), भारत की समेकित निधि से बहन किया जाने वाला व्यय है।

अतः, अब, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा (7) के प्रावधानों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को एतद्वारा आधार बच्चों द्वारा आधार धारित करने अथवा आधार प्रमाणन का प्रमाण देना अपेक्षित है और योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के संवितरण को बच्चे के आधार के धारण अथवा आधार प्रमाणन की प्रक्रियाधीन, जैसा मामला हो, से जोड़ा जाएगा और बच्चे से आधार प्रपत्र संग्रह अथवा उन्हें प्रमाणित करने का दायित्व, बच्चे के अभिभावकों या अभिरक्षकों के समन्वय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य का होगा।

2. उक्त योजना के तहत लाभ लेने वाले ऐसे बच्चों को, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधारनामांकन के लिए आवेदन करना होगा और यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की पात्र है, विद्यालय का प्राचार्य यह सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि इन बच्चों को उनके आधार नामांकन के लिए निकटतम आधार नामांकन केन्द्र (सूची "www.uidai.gov.in" पर उपलब्ध हैं) पर ले जाया जाए।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य ने विद्यालय शिक्षा विभाग अथवा इस योजना का संबंधित विभाग (यहां इसके बाद "विभाग" कहा गया है) को ऐसे बच्चों के लिए नामांकन सुविधाएं देना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, विभाग, यूआईएडीआई के मौजूदा पंजीयकों के संबंध में किसी सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधाएं सुझाया कराएगा। यूआईएडीआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक बच्चे को आधार आवंटित किया जाए, बच्चे को, बच्चे अथवा अभिभावक अथवा अधीरक्षक, जैसा मामला हो द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जाएगी।

(क) (i) यदि बच्चे ने नामांकन किया है, उसके आधार नामांकन पहचान स्लिप; अथवा

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके आवेदन की छायाप्रति, जैसा पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है

(ख) (i) फोटोग्राफ सहित बैंक की पासबुक; अथवा (ii) स्कूल के प्राचार्य अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र; अथवा (iii) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2 (1) लाभार्थियों को सहज और निर्बाध सब्सिडी या लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपने क्षेत्रीय एककों और विद्यालयों के जरिए निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, नामतः

(2) बच्चों और उनके अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को उक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया और विद्यालयों में व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को परामर्श दिया जाए कि यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं कराया है, अपने बच्चों का अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन कराने के लिए 30 जून, 2017 तक नामांकन कराएं।

(3) यदि लाभार्थी विद्यालय अथवा अपने निवास स्थल के आस-पास नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण वे नामांकित होने की वजह से नामांकन नहीं करा पाए हों, विभाग से अपेक्षा है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा सृजित करें और बच्चों और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने वेब-पोर्टल पर अपने नाम और अन्य व्यौरा जैसे स्कूल का रोल नः अथवा कक्षा विवरण, विद्यालय का नाम, पता, मोबाइल न. देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध पंजीकृत करें और ये अनुरोध पंजीकृत विद्यालयों के पास भी पंजीकृत किए जाएं।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू- कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-5/2016-एस एस (खंड-II)-पार्ट]

डी. के. गोयल, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

S.O. 475(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (the Scheme) involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section (7) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Children receiving benefit under the aforesaid Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication and the disbursement of incentive amount under the Scheme shall be linked to possession of Aadhaar by the children or had undergone Aadhaar authentication, as the case may be, and the responsibility to collect Aadhaar from children or to authenticate them, as the case may be, shall be on the Principal of the School concerned, in coordination with parents or guardians of the children.

(2) Children receiving benefits under the aforesaid Scheme who are not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 and in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, the Principal of the School shall ensure and make arrangement to ensure that such children are taken to the nearest Aadhaar Enrolment Center (list available at "www.uidai.gov.in") for enrolling them for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the School Education department or the department dealing with the aforesaid Scheme in the State (herein after called 'department') is required to offer enrolment facilities for the children who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar Enrolment Centers located in the vicinity, the department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the children, incentive amount shall be sanctioned to the children, subject to the production of the following documents by the parent or guardian, as the case may be, namely:—

- (a) (i) if the child has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Photo Identity Card issued by the Principal of the School or Tehsildar; or (iii) any other document specified by the State Education Department.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free subsidy or benefits to the beneficiaries, department through their field units and schools shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(2) Wide publicity through media and individual notices at schools shall be given to children and their parents or guardians to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the incentive amount under the aforesaid Scheme and the parents or guardians may be advised to get their children enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within vicinity from the school or where they reside, the department is required to create enrolment facilities at convenient locations and the children and their parents or guardian may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, school roll number or class details, school name, address, mobile number on their web portal and such requests may also be registered with the schools.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-5/2016-SS (Vol.II)-Pt.]

D. K. GOEL, Dy. Secy.